Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
May 2024 5(5), 999–1003

NATIONAL EDUCATION POLICY 2020: TOWARDS THE CREATION OF NEW INDIA: THE CHALLENGES AND POSSIBILITIES OF EDUCATION

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: नये भारत के निर्माण की दिशा में : शिक्षा की चुनौतियाँ और संभावनाएँ

Dr. Dipika Sharma [1], Dr. Neha Singh [2]

[1] Assistant Professor, Delhi University
[2] Assistant Professor, Ramanujan College, Delhi University

Corresponding Author

Dipika Sharma,
dr.dipika1982@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.2614

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

ABSTRACT

English: 'Deshbhakti Dadati Rashtriyam L' (Bhagavad Gita)
That is, patriotism leads to patriotism.
"Vidya distribution science memory: readiness
That is, "Vidya, logic, science, memory, readiness, and functionality, these six, nothing is incurable for the one who has."
The importance and relevance of education can be understood by this formula. It cannot be denied that the level of education determines the foundation of any country. That is, the stronger the foundation is, the stronger and the internal strong. If you see the history of ancient India, then in India, when education was given through Gurukuls. At that time, the country was strong in the field of knowledge and in the economic field. This is the reason that India of that era was called the golden bird and the name of India was also the title of the world guru. The education system, which changed time and implemented by English, pushed India back to knowledge, but economically as well as intellectual sector. Now even if physical progress is visible, India is lagging behind in economic progress. After more than the year of independence, it was now conceived that the medium of education was approved. The foundation of India was strengthened since the long churn of the National Education Policy 2020.

Hindi: 'राष्ट्रभक्ति ददाति राष्ट्रनिर्माणम् ।' (भगवद्गीता)
अर्थात् राष्ट्रभक्ति से राष्ट्रनिर्माण होता है।
"विद्या वितर्कों विज्ञानं स्मृतिः तत्परता क्रिया। यस्यैते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमतिवर्तते ।।"
अर्थात - "विद्या, तर्कशक्ति, विज्ञान, स्मृतिशक्ति, तत्परता, और कार्यशीलता, ये छह जिसके पास हैं, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं ।"
इस सूत्र से शिक्षा की महत्वता और उसकी प्रासंगिकता को समझा जा सकता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा का स्तर ही किसी भी देश की नींव का निर्धारण करता है। यानि नींव जितनी मजबूत होगी वह उतना ही सशक्त और आंतरिक रूप से मजबूत होगा। प्राचीन भारत का यदि इतिहास देखे तो भारत में जब शिक्षा गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। उस दौर में देश ज्ञान के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में मजबूत था। यही वजह है कि उस दौर के भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत के नाम विश्व गुरु का तमगा भी था। समय बदलने और अंग्रेजी के द्वारा लागू की गयी शिक्षा प्रणाली ने भारत को ज्ञान, लेकिन बौद्धिक क्षेत्र के साथ ही आर्थिक रूप से पीछे धकेल दिया। अब भौतिक प्रगति भले ही दिख रही हो आर्थिक प्रगति में भारत पीछे है। आजादी के साल से ज्यादा का समय होने के बाद अब इस बात की परिकल्पना की गयी कि शिक्षा के माध्यम को मंजूरी मिल पायी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लंबे मंथन के बाद से ही भारत की नींव को मजबूत किया गया।

Keywords: National Education Policy, Modern India, Sustainable Development Agenda 2030, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आधुनिक भारत, सतत विकास एजेण्डा 2030

How to cite this article (APA): Sharma, D., and Singh, N. (2024). National Education Policy 2020: Towards the Creation of New India: The Challenges and Possibilities of Education. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 5*(5), 999–1003. doi: 10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.242

1. प्रस्तावना

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आलौकिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर सापीय शिक्षा वह उचित माध्यम हैं, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओ को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत्त विकास एजेण्डा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी)

वैश्विक शिक्षा विकास एजेण्डा के अनुसार विश्व में 2030 तक 'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत् विकास के लिए 2030 एजेण्डा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त किए जा सकें।

"समृद्धि ददाति राष्ट्रनिर्माणम् ।”

(महाभारत)

अर्थात् समृद्धि से राष्ट्रनिर्माण होता है। शिक्षा में सुधार और रोजगार के अवसर*: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव किए जा सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है? [1]

डिजिटल शिक्षा और तकनीकी

अधिगम नीति में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए क्या तकनीकी साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं और कैसे शिक्षकों को इसके लिए तैयार किया जा सकता है?

- *सामाजिक और आर्थिक समानता*: नीति में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव किए जा सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है?

- *शिक्षा और उद्योग के बीच संबंध*: नीति में शिक्षा और उद्योग के बीच संबंध को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है?

- *शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार*: नीति में शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है?

मुख्य बिंदु

1. शिक्षा में सुधार 2. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा 3.सामाजिक और आर्थिक समानता 4.शिक्षा और उद्योग के बीच संबंध 5.अनुसंधान और नवाचार

2. परिचय

भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है, जिससे नये भारत के निर्माण में मदद मिल सके।राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मंथन का दौर - आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का खाका तैयार करने के लिये पूरे देश से विचार और राय ली गयी। देश की लगभग 2 लाख ग्राम पंचायते 5 जिलों में मंथन का दौर चला। इन 650 स्थान 6600 ब्लॉक को अलग-अलग लोगों की राय ली गयी। शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापक स्तर पर छात्रों से भी सुझाव लिए गये। सभी सुझावों को संकलित कर फिर प्रारूप तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदु

1. शिक्षा मंत्रालय इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने का प्रावधान किया गया। इस मंत्रालय के माध्यम से शिक्षित करने और शिक्षा देने का ही है।

२. शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख आयाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था के गार प्रमुख आश्रम फिर्तरित कि जिसमे विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम और बांचागत सुविधाएं है।

3. मातृभाषा में पढ़ाई मातृभाषा में पढ़ाई अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में मातृभाषा का विशेष है। जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है और उसके सीखने की गति मी बढ़ती है। अनुसार बालक अपनी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में सरलता एवं शीघ्रता से सीखता है। इसी काही ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाई विविधता को महत्व दिया गया है।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कर माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे कक्षा आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषा की पढ़ाई सेकेण्डरी लेवल से होगी। शेष विषय चाहे वह अंग्रेजी में ही क्यों ना हो. एक विषय के तौर पर ही पढ़ाया जायेगा।

5. सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा का प्रावधान कर विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ने रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6. सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा- प्री/बालवाटिका / वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आगनबाड़ी 3 वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल के माध्यम से मुफ्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

7. प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि पूर्ण बनाने का प्राथमिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद रविन्द्र नाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। जिससे विद्यार्थियों को जहाँ तक संभव हो रित्या स्रोत से ज्ञान प्राप्ति का मौका मिलेगा।

8. नये प्रावधान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+5 के ढांचे की जगह 2+3+3+ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सरचना 4 को लागू करने का प्रावधान किया गया जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 उम्र के बच्चों के लिए हैं। इसमें अब तक दूर रखे गये 3 साल के बच्चों को स्कूली 6 पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है।

9. शारीरिक शिक्षा विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्यमा आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें। राष्ट्रीय प्रणाली में प्री स्कूलिग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और तीन साल की आगनबाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए तीन साल की प्री-प्राइमरी और पहली तथा दूसरी कक्षा को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और पाचवी कक्षा को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्रा केवल तीसरी, पांचवी और आठवी कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केन्द्र परख समग्र प्रदर्शन-विकास के लिए कार्य आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। आंगनबाड़ी स्कूल के माध्यम से मुफा सुरक्षित और तनावपूर्ण बालवाड़ी और प्री-शिक्षा की संकल्पना है।

अन्य प्रावधान:

1.छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स, इंटर्नशिप करवाई जाएगी।

2.म्यूजिक और आईस को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.उच्च शिक्षा में भी कई तरह के बदलाव किए गए है। अगर कोई छात्रा दूसरे कोर्स में जाना बाहती है तो निश्चित समय तक ब्रेक लेकर जा सकती है।

4. रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए चार साल की डिग्री और नौकरी करने वालों के तीन साल की विधी।

5.ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में होगे।

6. पिछड़े वर्षों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी प्रावधान पाठ्यक्रकम और मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम है. जिसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने और छात्रों के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चितन को बढ़ावा देना है। जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ इंटर्नशिप भी होगी।

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों पर पाठ्यक्रम पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की रूपरेखा तैयार की जाएगी। छात्रओं के समय विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव के रूप में भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्याकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमता (आधारित सॉफ्टवेयर) का प्रयोग किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चार महत्वपूर्ण चरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चार चरणों को शामिल किया गया। इन चार चरणों में फाउण्डेशन स्टेज प्रीपेटरी स्टेज मिडिल स्टेज और सैकेण्डरी स्टेज प्रमुख है। फाउण्डेशन स्टेज: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फाउण्डेशन स्टेज में 3 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया

गया है। जिसमें 8 से 3 की प्री स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत छात्रों का भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास में ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। प्रीपेटरी स्टेज: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक के 8 से 11 वर्ष के छात्रों का संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। वहीं सभी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा।

मिडिल स्टेज इस स्टेज के भीतर छठवीं से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जिसमें छठवीं कक्षा के बच्चों से ही कोडिंग सिखाना शुरू किया जाएगा। वहीं सभी बच्चों को व्यावसायिक परीक्षण के साथ-साथ व्यवसाय इंटरर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

सैकेण्डरी स्टेज इस स्टेज में आठवीं कक्षा से 12वीं कक्षा के 12वीं तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इस स्टेज के भीतर आठवीं से शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी खत्म करके बहु वैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी मनपसंद के अनुसार अपने विषयों को चुन सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को विषयों को चुनने को लेकर स्वतंत्रता दी गई है. छात्र साइस के विषयों के साथ साथ आर्टस या कॉमर्स के विषय को भी एक साथ पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तय किये गये लक्ष्य:राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषाओं को लेकर कई विकल्प रखे गए है।

यदि शैक्षिक पाठ्यक्रम में कोई छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा को पढ़ना चाहता है तो वह आसानी से उन्हें पड़ सकता है। वहीं इस शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का भी विकल्प छात्रों के समक्ष रखा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन तक के सभी छात्रों के लिए

संख्यात्मक ज्ञान तथा साक्षरता को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी।

स्वास्थ्य नीति के तहत छात्रों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिसके साथ छात्रों के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी बनाये जाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिवक्षकों को समय-समय पर उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति को भी रखा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापन के लिए बी.एड. की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में सम्मिलित कर दिया गया है। यानी 2030 तक बी.एड. का कोर्स 4 साल का हो चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भीतर हायर एजुकेशन से संबंधित एम.फिल. की डिग्री को भी खत्म किया पा रहा है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम की चर्चा की विषयवस्तु को भी तैयार किया जाएगा।

छात्रओं को जिरा क्षेत्र में अधिक रूचि है जैसे खेल, कला, बॉक्सिंग आदि में छात्रों को बढ़ावा दिया

जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा वहीं मेन सिलेबस में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जा रहा है।

छाव्य पर वाई का बोझ कम करने के लिए हरसंभव कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। जिसमें पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शैक्षिक पाठ्यक्रम में किया जाएगा।

छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं का बोझ करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को भी बदला जाएगा जिसमे 1 साल में दो बार छात्रों की परीक्षाएँ की जाएंगी।

छात्रओं को ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पाठ्यक्रम / कोर्स उपलब्ध करवाए जाएगे।

महाविद्यालयों की स्वायत्ता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी तथ्था क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी।

देश के बड़े संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम के लिए वैश्विक स्तर पर मानकों हेतु बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कराई जाएगी।

वहीं कानूनी तथा चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक कल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।

शैक्षिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा उसे तकनीकी माध्यम से जोडने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी जिससे शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान संभव हो सकें।

3. निष्कर्ष

शिक्षा के संबंध में गाधीजी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जरूरी हो जाता है कि पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन कर उसे किसी

प्रकार एक नए बदलाव के रूप में रखा जाए। सबसे अहम बात बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार, नवाचार और अनुसंधान की राष्ट्रीय तकनीकियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता थी भारतीय शिक्षण व्यवत्या की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक, साहसिक एवं दूरगामी दृष्टिकोण का कार्य है। आज भारत ज्ञान-विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया जा चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभावी होगी और यह नए भारत की मजबूत और प्रभावी नीव सिद्ध होगी।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Bhagavad Gita

Drishti The Vision (Critical Issues) National Education Policy 2020. National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

Prakash Kumar, National Education Policy will meet the demands of the 21st century, Outlook Hindi, 24 August 2020 Prof. K.L. Sharma Dainik Bhaskar Jaipur Edition, Pus 2. 24 August 20201

National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

Gangwal Subhash National Education Policy will meet the challenges of the 21st century, Pus. Singh Durgesh, Chronicle Monthly Magazine, May 2020, Pus: 80-811